RPSC Main Exam 2024 : Test Series

Assistant Engineer

विषय : हिन्दी –1

(संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, निबंध लेखन)

अनिवार्य प्रश्न पत्र : 10 | परीक्षा की तिथि : 18-01-2026

विस्तार–पूर्ण उत्तर

1. (क) (i) उत् + लंघन = उल्लंघन (ii) निः + छल = निश्छल

(iii) अभि + उदय = अभ्युदय (iv) नमः + ते = नमस्ते

(ख) (i) संभव = सम् + भव (ii) परिणय = परि + नय

(iii) महोदय = महा + उदय (iv) निस्तार = निः + तार

2. (क) (i) परम है जो आनन्द = परमानंद (ii) कमल के सदृश्य चरण = चरणकमल

(iii) शोक से ग्रस्त = शोकग्रस्त (iv) राज्य का अध्यक्ष = राज्याध्यक्ष

(ख) (i) महात्मा = महान आत्मा है जो (ii) गुरूदक्षिणा = गुरू के लिए दक्षिणा

(iii) चक्रधर = चक्र को धारण करता है जो (iv) जलज = जल में उत्पन्न होता है जो

3. (क) (i) अति = अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यन्त, इत्यादि।

(ii) सु = सुकर्म, सुगम, सुलभ, स्वागत, इत्यादि।

(ख) (i) अभिमुख = मुख के समीप (ii) पुराकाल = पूर्वकाल में

(iii) प्राक्कथन = पहले का कथन (iv) दुर्व्यवहार = बुरा व्यवहार

4. (क) (i) आवट = लिखावट, सजावट, बनावट, मिलावट, इत्यादि।

(ii) इया = बढ़िया, घटिया, भइया, रसिया, इत्यादि।

(iii) ई = बोली, चोरी, खुशी, बुद्धिमानी, भारी, देशी, धनी इत्यादि।

(iv) पन = लड़कपन, बालपन, पागलपन, बचपन, इत्यादि।

(ख) (i) भूखा = आ (ii) टोकरी = री

(iii) लुटेरा = एरा (iv) डकैत = ऐत

5. (क) (i) कोयल = कोकिल, मदनशलाका, कलघोष, काकपाली, इत्यादि।

(ii) चन्द्रमा = इन्दु, शशि, शशांक, हिमांशु, विभाकर, इत्यादि।

(ख) (i) अनुराग = विराग (ii) उत्थान = पतन

(iii) थोक = खुदरा (iv) प्रकट = गुप्त

6. (i) अकथ = जिसके विषय में कुछ कहा न जा सके; अथक = जो थके नहीं।

(ii) अन्न = अनाज; अन्य = दूसरा

(iii) अपेक्षा = आकांक्षा, अभिलाषा; उपेक्षा = तिरस्कार, अवहेलना

(iv) चरम = सबसे अधिक; चर्म = चमड़ा

7. (i) दोपहर के बाद का समय = अपराह्न (ii) जिसे किसी बात का पता न हो = अनभिज्ञ, अज्ञ

(iii) सत्व गुण से युक्त = सात्विक (iv) जो स्त्री विद्वान हो = विदुषी

(v) शत्रुओं को मारने वाला = शत्रुध्न (vi) जो बायें हाथ से काम करता हो = सव्यसाची

(vii) जो क्षमा पाने योग्य है = क्षम्य (viii) सब कुछ खाने वाला = सर्वभक्षी

8. (i) निस्वार्थ = निःस्वार्थ (v) आधीन = अधीन

(ii) वालमिकी = वाल्मीकि (vi) जागृत = जाग्रत

(iii) गंवार = गँवार (vii) अंजली = अंजलि

(iv) उर्त्तीण = उत्तीर्ण (viii) अत्याधिक = अत्यधिक

9.	अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(i)	यहाँ कोई एक चित्र नहीं है।	यहाँ कोई चित्र नहीं है।
(ii)	केवल चार रूपया मात्र दीजिए।	केवल चार रूपया दीजिए।
(iii)	उसका प्राण निकल चुका है।	उसके प्राण निकल चुके है।
(iv)	मैंने गुरू का दर्शन किया।	मैंने गुरू के दर्शन किए।
(v)	उसे मृत्यु का दण्ड की सजा मिली।	उसे मृत्यु दण्ड मिला।
(vi)	राधा एक विधवा स्त्री है।	राधा एक विधवा है।
(vii)	उसने कल मुझे गाली दिया।	उसने कल मुझे गाली दी।
(viii)	यह आँखो से देखी घटना है।	यह आँखों देखी घटना है।

10. (i) **अगर–मगर करना (टालमटोल करना)** → वह पैसे वापस देने से हमेशा अगर–मगर करता है।

(ii) **अन्न न लगना (खाकर भी सेहत नहीं बनना)** → पौष्टिक भोजन के बावजूद उसके शरीर में अन्न नहीं लगता।

(iii) **इतिश्री होना (समाप्त होना)** → महात्मा गाँधी की मृत्यु के साथ ही एक युग की इतिश्री हो गई।

(iv) **आँखों में बसना (अत्यन्त प्रिय होना)** → पार्थ अपने पिता के आँखों में बसा है।

(v) **उठ जाना (मर जाना)** → सड़क दुर्घटना में वह इस संसार से उठ गये।

(vi) **उन्नीस होना (कमतर होना)** → डोनाल्ड ट्रंप बुद्धि में पुतिन से उन्नीस है।

(vii) **कंचन बरसना (अत्यधिक धन का लाभ होना)** → मेरी पुत्री के जन्म के बाद मेरा व्यापार चमक उठा और घर में कंचन बरसने लगा।

(viii) **खेत रहना (वीरगति प्राप्त करना)** → महाभारत के युद्ध में अनगिनत वीर खेत रहे।

(ix) **गाँठ बाँधना (याद रखना)** → मेरी बात गाँठ बाँध लो, चापलूस लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये।

(x) **चूड़ियाँ पहनना (डरपोक होना)** → तुम रणक्षेत्र से भाग आये, अब चूड़ियाँ पहन लो।

(xi) **टोपी उछालना (अपमानित करना)** → वह अपने परिजनों का सबके सामने टोपी उछालता रहता है।

(xii) **बाजार गर्म होना (अधिक प्रचार होना)** → आजकल रिश्वत का बाजार गर्म है।

11. (i) **अतिशय भक्ति, चोर के लक्षण (ढ़ोगी व्यक्ति चापलूस हुआ करते हैं)** → उससे दूर रहो, उसकी अतिशय भक्ति चोर के लक्षण लग रहे हैं।

(ii) **ऊधो का लेना न माधो का देना (अपने काम से मतलब रखना)** → वह केवल अपने काम से मतलब रखता है – न ऊधो का लेना न माधो का देना।

(iii) **ओस चाटे प्यास नहीं बुझती (बहुत कम संसाधन से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती)** → अपनी बहन की शादी में इतना खर्च करने के बाद भी ऐसा लगा कि ओस चाटकर भी प्यास नहीं बुझी।

(iv) **एक लकड़ी से सबको हाँकना (सभी के साथ समान व्यवहार करना)** → इस नेता की नज़र में सब बराबर है। यह एक ही लकड़ी से सबको हाँकता है।

(v) **काला अक्षर भैंस बराबर (निरक्षर मनुष्य)** → उसके लिए वेद–उपनिषद काला अक्षर भैंस बराबर ही है।

(vi) **खाली दिमाग शैतान का घर (बेरोजगार को खुराफातें सुझती है)** → तुम्हें नौकरी करना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर।

(vii) **गढ़े कुम्हार भरे संसार (एक की कृति से अनेक लोगों का लाभ उठाना)** → ओशो के विचार से लाभान्वित होने वाले लोगों को देखकर यह लगता है कि गढ़े कुम्हार भरे संसार।

(viii) **घर पर फूस नहीं नाम धनपत (निरर्थक नाम)** → वह व्यक्ति लाखों का मालिक है, पर घर में हमेशा कलह रहती है।

(ix) **चमड़ी जाय पर दमड़ी ना जाय (अत्यधिक कंजूस)** → सेठ करोड़ीमल को भले पैदल चलना पड़े लेकिन वे एक भी पैसा खर्च नहीं करते, इसे ही कहा गया है–चमड़ी जाय पर दमड़ी ना जाय।

(x) **जड़ काटते जाएँ, पानी देते जाएँ (भीतर से दुश्मन, ऊपर से दोस्त)** → कुछ प्रभावशाली देश भारत के साथ जड़ काटकर पानी देने वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं।

(xi) **जस दूल्हा तस बनी बारात (बुरों का बुरों के साथ मिलना)** → दुष्टों को साथी मिल ही जाता है, जैसे जस दूल्हा तस बनी बारात।

(xii) **डंडा सब का पीर (सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं)** → पुलिस द्वारा कर्फ्यू लगा देने से पूरे शहर की स्तिथि नियंत्रण में हो गयी क्योंकि डंडा सबका पीर होता है।

12. (i) Apartheid → रंगभेद

(ii) Voluminous → विशालकाय

(iii) Treason → राजद्रोह

(iv) Sub-clause → उपधारा

(v) Perpetual → निरंतर, सतत

(vi) Modus operandi → कार्य–शैली

(vii) Hindrance → बाधा

(viii) Directorate → निदेशालय

(ix) Biennial → द्वि–वार्षिक

(x) Armistice → युद्ध–विराम

(xi) Capitalism → पूँजीवाद

(xii) Glossary → शब्दावली

(xiii) Incognito → अज्ञात, गुप्त वेश में

(xiv) Monopoly → पूर्ण एकाधिकार

(xv) Questionnaire → प्रश्नावली

(xvi) Per capita → प्रति व्यक्ति

© Copyright: MADE EASY

13. **निबंध लेखन :**

(i) वैश्वीकरण और संरक्षणवाद

वैश्वीकरण का आशय विश्व अर्थव्यवस्था में खुलापन, बढ़ती आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के विस्तार से लगाया जाता है। वैश्वीकरण के तहत विश्व बाज़ारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता की स्थिति उत्पन्न होती है तथा देश की सीमाओं को पार करते हुए व्यवसायों का स्वरूप विश्वव्यापी हो जाता है। वैश्वीकरण के तहत ऐसे प्रयास किये जाते हैं कि विश्व के सभी देश व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में एक–दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर सकें। परंतु वर्तमान समय में वैश्वीकरण के प्रयासों के मध्य संरक्षणवाद ने पनाह ले ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो स्वंय को वैश्वीकरण का पैरोकार कहता था, आज संरक्षणवादी नीतियों को प्रश्रय देने लगा है।

गौरतलब है कि वैश्वीकरण एवं संरक्षणवाद एक–दूसरे की विपरीत अवधारणाएँ हैं। वैश्वीकरण स्वतंत्र व्यापार पर आधारित होता है, जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वतंत्र व्यापार होता है। परंतु इसके विपरीत संरक्षणवादी नीति में विदेशी उत्पादों के साथ भेदभाव कर उनकी कीमतों या मात्रा आदि को दुष्प्रभावित किया जाता है। इसकी वजह विदेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में कमी एवं उनके बदले स्वदेशी उत्पादों की मांग में वृद्धि करनी होती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरक्षण के अनेक तरीके प्रचलन में हैं। संरक्षण का प्रथम तरीका है विदेशी उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि करना। हम देखते है कि आयात शुल्क बढ़ जाने से विदेशी उत्पाद, घरेलू उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाते हैं तथा उनकी मांग कम हो जाती है। संरक्षण का दूसरा तरीका है कोटा निर्धारण। इसके तहत सरकार आयातित वस्तुओं की अधिकतम मात्रा का निर्धारण करती है एवं इस निर्धारित मात्रा से अधिक वस्तुओं का देश में आगमन प्रतिबंधित हो जाता है। इस प्रकार घरेलू उद्योग उन वस्तुओं की प्रतिस्पर्द्धा से बच जाते हैं। संरक्षण का तीसरा तरीका घरेलू उत्पादों को सहायता देकर उनकी कीमतों में कमी लाना है। इससे इन उत्पादों की कीमत विदेशी उत्पादों की तुलना में कम हो जाती है एवं वे सस्ते हो जाते हैं और उनकी मांग में वृद्धि हो जाती है।

अगर वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो हम पाते हैं कि मौजूदा समय में व्यापार युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन जैसे देश अपनी संरक्षणवादी नीतियों के कारण विश्व व्यापार संगठन के नियमों को भी धता बता रहे हैं। मौजूदा व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि पिछले कई वर्षों से तैयार हो रही थी। अमेरिका द्वारा आायात कर में की गई वृद्धि को विश्व समुदाय द्वारा संरक्षणवादी रवैया करार दिया गया। गौरतलब है कि अमेरिका अपने द्वारा उठाए गए इस कदम को न तो स्वतंत्र व्यापार के खिलाफ मानता है और न ही वैश्वीकरण के विरुद्ध।

अमेरिका का तर्क है कि विश्व के अनेक देशों ने अपने यहाँ आयात कर की दर काफी ऊँची कर रखी है, जबकि अमेरिका में यह काफी नीची है। ऐसे में वह मानता है कि वैश्विक स्वतंत्र व्यापार संतुलित नहीं है क्योंकि दूसरे देशों के उत्पाद तो अमेरिका में काफी सुगमता से कम कीमतों पर आ जाते हैं, जबकि अमेरिकी उत्पादों के साथ दूसरे देशों में काफी भेदभाव होता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति वर्तमान में 'अमेरिका प्रथम' की नीति का पालन कर रहे है जिसके अनुसार अमेरिकी हितों की पूर्ति पहले होनी चाहिये एवं अन्य देशों के हितों का संरक्षण उसके बाद में होना चाहिये। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह नीति अमेरिकी उद्योगों की मंद विकास गति को तीव्र करने तथा वहाँ की बेरोज़गार जनता को रोज़गार दिलाने एवं

अमेरिकी आर्थिक संवृद्धि को तीव्र करने हेतु लाई गई है। अमेरिका के संरक्षणवादी रुख को उसके सामरिक सुरक्षा जैसे हितों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

इस व्यापार युद्ध के विश्व में गंभीर आर्थिक–राजनीतिक दुष्परिणाम निकलने की आशंका जताई जा रही है। इस व्यापार युद्ध से विश्व पुनः वैश्विक आर्थिक मंदी की ओर जा सकता है। स्वतंत्र प्रतिस्पर्द्धा खत्म होने से उत्पादकता एवं उत्पादन में भी कमी आएगी। इस प्रकार संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाने से विश्व के उपभोक्ताओं को ऊँची लागत पर कम गुणवत्ता वाली वस्तुएँ प्राप्त होंगी।

व्यापार युद्ध के सकारात्मक पक्ष को देखने वालों का मानना है कि इससे दीर्घकाल में परस्पर सहयोग में वृद्धि होगी। यह व्यापार युद्ध वर्तमान आयात कर की विभेदी संरचना में समानता लाएगा एवं विश्व व्यापार संगठन (WTO) को और मज़बूत बनाएगा।

स्वतंत्र व्यापार की विसंगतियों को वैश्विक मंच से समावेशी दृष्टिकोण द्वारा ही दूर किया जा सकता है और तभी विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्था को पारदर्शी एवं परस्पर सहयोगी बनाया जा सकेगा।

(ii) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु में आने वाले परिवर्तन के प्रभाव को एक सीमित क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है तथा पूरी दुनिया में भी इसके प्रभाव दिखने लगे हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर दशा में पहुँच रही है और पूरे विश्व पर इसका असर देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ–साथ वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के भौतिक संकेतों – जैसे भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और बर्फ के पिघलने के अलावा सामाजिक–आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य, प्रवास और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा और भूमि तथा समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया गया है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने, अनुकूलन करने और उससे उबरने में समुदायों, पारिस्थितिकी तंत्रों, बुनियादी ढाँचे और बड़े पैमाने पर समाज जैसी विविध प्रणालियों की सामूहिक क्षमता को जलवायु परिवर्तन के प्रति आघात सहनीयता कहते हैं। इसमें जलवायु दशाओं में बदलाव के कारण होने वाले तनाव और दबाव को बिना किसी महत्वपूर्ण व्यवधान या क्षति के झेलने की क्षमता शामिल है, जिससे इन प्रणालियों की चुनौतियों की दशा में भी कार्यशीलता बनी रहती है।

मूल रूप से, जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दीर्घावधि में ताप और मौसम के प्रतिरूप में होने वाले स्थायी परिवर्तनों से है। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारकों जैसे– सौर सक्रियता में बदलाव अथवा बड़े ज्वालामुखीय उद्गार से प्रभावित हुआ है किंतु 1800 के बाद से जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियाँ रही हैं। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। ये गैसें ऊष्मा प्रग्रहित करती हैं, जिससे वैश्विक ताप बढ़ता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रति आघात सहनीयता हेतु वैकल्पिक तकनीकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने और उसके अनुकूल होने के उद्देश्य से समाधानों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है। 'ग्लोबल वार्मिंग' के प्रभाव में तीव्रता और विस्तार के साथ जलवायु परिवर्तन का सामना करने की अनिवार्यता और भी स्पष्ट होती जा रही है। इसके प्रभावों की बढ़ती गंभीरता जलवायु परिवर्तन के प्रति आघात सहनीयता को वर्द्धित करने में वैकल्पिक तकनीकों की महत्ता को रेखांकित करती है।

जलवायु परिवर्तन से भारत के लिये गंभीर चुनौतियाँ हो सकती हैं, जिसका प्रभाव कृषि, जल संसाधन, जैवविविधता और मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। आघात सहनीयता में वर्द्धन करने के लिये, भारत को ऐसी नवीन तकनीकों की आवश्यकता है जिससे सतत् विकास को बढ़ावा देते हुए जलवायु जोखिमों का शमन संभव हो। भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षमता के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है किंतु अक्षय ऊर्जा का विद्युत् वितरण तंत्र में विस्तार और एकीकरण करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

भारत में जल की कमी एक गंभीर समस्या है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले सूखे और वर्षा के अनियमित प्रतिरूप के कारण और भी गंभीर हो गई है। ड्रिप सिंचाई और परिशुद्ध कृषि जैसी वैकल्पिक तकनीकें कृषि में जल दक्षता को बढ़ा सकती हैं, जिससे जल की खपत कम हो सकती है और फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है।

भारत का तेज़ी से शहरीकरण बुनियादी अवसंरचना पर दबाव, वायु प्रदूषण और जलवायु–संबंधी आपदाओं के प्रति सुभेद्यता के मामले में चुनौतियाँ पेश करता है। शहरी हरित स्थान और पारगम्य फुटपाथ जैसे प्रकृति–आधारित समाधान नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभावों को कम करते हैं तथा बाढ़–आघातसहनीयता को बढ़ाते हैं, जिससे सतत् शहरी विकास को बढ़ावा मिलता है।

भारत में जलवायु तन्यकता बनाने के लिये ऐसे अभिनव समाधानों की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास का पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सामंजस्य स्थापित करें। वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ जलवायु–अनुकूल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन, कुशल जल प्रबंधन, संधारणीय कृषि और आघातसह शहरी बुनियादी अवसंरचना की ओर एक मार्ग प्रदान करती हैं। हालाँकि, उनकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिये सहायक नीतियों, संस्थागत क्षमता निर्माण और हितधारक सहयोग की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, भारत समावेशी और सतत् विकास को बढ़ावा देते हुए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सकता है।

सरकारी एजेंसियों, शोध संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों को नवाचार को बढ़ावा देने तथा वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिये मिलकर काम करना चाहिये। संसाधनों, विशेषज्ञता और ज्ञान को संगठित करके ये सहयोगी प्रयास तकनीकी अभिग्रहण की गति को तेज़ कर सकते हैं और जलवायु तन्यकता की दिशा में सार्थक प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं।

(iii) राजस्थान में सिंचाई का महत्व

राजस्थान का नाम सुनते ही प्रदेश के विभिन्न हिस्से में रह रहे लोगों के जेहन में रेतनुमा इलाके की छवि में आती है और यह माना जाता है कि राजस्थान की ज्यादातर भूमि खेती योग्य नहीं है। कभी यह सच था, लेकिन अब यह मिथक टूट रहा है। राज्य में भले पानी की कमी हो, लेकिन यहां पानी बचाने का काम भी व्यापक स्तर पर चल रहा है। अगर हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पर गौर करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल करीब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर

जिले पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं और यह सीमा करीब 1070 किलोमीटर है। राज्य का उत्तर–पश्चिमी इलाका रेतीला है, तो मध्य–पर्वतीय एवं दक्षिण–पूरब का हिस्सा पठारी है। सिर्फ पूर्वी हिस्सा मैदानी है।

यहां की प्रमुख फसल मक्का, ज्वार, गेहूं, चना एवं अन्य दलहनी फसलें मानी जाती हैं लेकिन अब करीब–करीब हर फसल यहां उग रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सिंचाई योजनाओं का विस्तार है।

केंद्र सरकार सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद मुहैया करा रही है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों को लाभान्वित कर रही हैं।

राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहां बूंद–बूंद सिंचाई (फौव्वारा प्रणाली) सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि ज्यादातर खेत ऐसे हैं कि इनमें पानी रुकना संभव नहीं है। इस प्रणाली के विकसित होने के बाद किसानों ने असमतल भूमि पर भी खेती करना शुरू कर दिया है। यह प्रणाली जहां हर तरह के खेत के लिए उपयोगी है वहीं इसके तहत सिंचाई व्यवस्था करने में ज्यादा लागत की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए भी किसान इस योजना के प्रति काफी आकर्षित हैं। बूंद–बूंद सिंचाई के लिए कनेक्शन भी प्राथमिकता के स्तर पर दिए जा रहे हैं। राज्य में जहां समुचित सिंचाई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं वहीं पानी बचाने की भी कोशिशें जारी हैं।

पानी की किसी भी कीमत पर दुरुपयोग न होने पाए, इसके लिए सबसे ज्यादा तवज्जो उन योजनाओं पर दी जा रही है, जिनके जरिए सिंचाई भी हो जाए और पानी का एक बड़ा हिस्सा भी बचा रहे। सरकार की कोशिश है कि इसे हर किसान तक पहुंचाया जाए, जिससे राज्य सभी प्रकार के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन सके तथा साथ ही यहां के किसानों की माली हालत में भी सुधार हो सके।

यह सच है कि संपूर्ण भारत में कुओं का जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार नए कुएं खुदवाने के साथ ही पुराने कुओं की उपयोगिता बनाए रखना चाहती है।

राज्य के किसानों की माली हालत को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की मदद से किसानों को डीजल पंपसेट वितरण कार्यक्रम चलाया। इसके तहत तय किया गया कि जो किसान आर्थिक रूप से डीजल पंपसेट खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें सरकार पंपसेट उपलब्ध कराएगी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

रेगिस्तान में नहरों से किसानों को पानी मुहैया कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा लग रहा था, लेकिन वर्षों की मेहनत के बाद अब यह सपना सच होता दिख रहा है। राज्य में नहरों का विकास भी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत 31 मार्च, 1958 में हुई। यह राजस्थान के उत्तर–पूर्व हिस्से में बहती है। इस परियोजना का असर पहली बार वर्ष 2001 में दिखा। हनुमानगढ़ जिले में रबी खाद्यान्न में शीर्ष पर पहुंचा तो गंगानगर तिलहन के मामले में अव्वल रहा। इस परियोजना के जरिए जहां कभी रेत के धोरे होते थे वहां नहर बन गई और लगभग 2000 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित भूमि में तब्दील हो गया। इस परियोजना से अब राज्य के साहवा, गजनेर, फलौदी, पोकरण और बांगरसर लिफ्ट परियोजनाओं के कुछ हिस्से में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खासतौर से चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं नागौर जिलों में इस नहर के पानी का प्रयोग होता है।

केन्द्र और राज्य सरकार के सामंजस्य से राजस्थान में किसानों को सिंचाई में काफी लाभ पहुँचा है जिससे आने वाले समय में खाद्यान्नों की उपज में बढ़ोत्तरी होगी।

(iv) डिजिटल अर्थव्यवस्था

डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग शामिल है, से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इससे नवाचार, उत्पादकता और समावेशिता की परिवर्तनकारी क्षमता प्राप्त होती है। यह धन सृजन के नए अवसर प्रदान करता है और सभी के लिये सूचना एवं बाज़ारों तक पहुँच को सुगम बनाता है किंतु इससे आर्थिक असमता भी बढ़ती है जो कि चिंता का विषय है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का समताकारी होना अथवा आर्थिक असमता का स्रोत होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें प्रौद्योगिकी, कौशल, नीतिगत मध्यवर्तन और बाज़ार की गतिशीलता तक पहुँच शामिल है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से, एक प्रबल समकारक के रूप में कार्य करने की क्षमता है। इससे भौगोलिक अवस्थिति और भौतिक अवसंरचना की आवश्यकता समाप्त होती है, जिससे व्यवसाय और व्यक्ति वस्तुतः किसी भी स्थान से वैश्विक बाज़ार में सक्रिय हो सकते हैं। बाज़ारों और सूचनाओं तक पहुँच को सभी के लिये सुलभ बनाने से विकासशील क्षेत्रों में लघु व्यवसायों और उद्यमियों को अपेक्षाकृत बड़ी, अधिक सुस्थित कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाता है, जिससे संबद्ध क्षेत्र में उनकी स्थिति में सुधार होता है।

भारत के डिजिटल पहचान कार्यक्रम, आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में क्रांति आई है। आधार से लाखों भारतीयों के लिये बैंक खाते खोलने और सरकारी सेवाओं का अभिगम सुनिश्चित हुआ है, जबकि UPI से ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान सहज और सुलभ हुआ है। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी भारत की ई–कॉमर्स की प्रमुख कंपनियों की सहायता से लघु व्यवसायों के लिये देश के ग्राहक वर्ग तक पहुँच स्थापित करना संभव हुआ है। ये प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के आवश्यक साधन और बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं।

कई कंपनियाँ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से बाज़ारों से जोड़ने, मध्यस्थों को कम करने और उनकी फसल के लिये बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल तकनीकों को प्रयोग में ला रही हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिये छोटे खुदरा विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों के लिये एक विवृत नेटवर्क प्रदान करके डिजिटल वाणिज्य को सभी के लिये सुलभ बनाना है।

एक समताकारी के रूप में अपनी क्षमता के बावजूद, डिजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक असमता को भी बढ़ा सकती है, विशेषकर जब डिजिटल संसाधनों तक पहुँच असमान रूप से वितरित होती है। "डिजिटल विभाजन", उन लोगों के बीच का अंतराल है जिनके पास इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों तक पहुँच है एवं जिनके पास नहीं है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में असमता का प्रमुख कारक है। विश्व के अनेक भागों, विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वाले क्षेत्रों में, हाई–स्पीड इंटरनेट तक पहुँच सीमित है। सीमित पहुँच की यह कमी व्यक्तियों और व्यवसायों को डिजिटल अवसरों का पूर्ण लाभ बाधित करती है और इस प्रकार मौजूदा आर्थिक असमताएँ और प्रबल होती हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का असमता के स्रोत के स्थान पर समताकारी स्रोत के रूप में इसकी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु सरकारों और संस्थानों को लक्षित नीतिगत मध्यवर्तन क्रियान्वित करने चाहिये। डिजिटल विभाजन को कम करना अत्यावश्यक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें वहनीय हाई–स्पीड इंटरनेट तक पहुँच का

विस्तार करना, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि हाशियाई समुदाय डिजिटल अवसरों का लाभ उठाने के लिये आवश्यक उपकरण से सन्नद्ध हों।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिये आवश्यक कौशल से श्रमिकों को लैस करने के लिये शैक्षिक सुधारों की भी आवश्यकता है। सरकारों को भविष्य की नौकरियों के लिये कार्यबल को तैयार करने के लिये विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में STEM शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिये। तेज़ी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल श्रमिकों की मदद करने के लिये आजीवन अधिगम के कार्यक्रम और पुनः कौशल पहल भी आवश्यक हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में सभी के लिये सूचना, बाज़ार और अवसरों तक पहुँच को सुगम बनाकर एक समताकारी के रूप में कार्य करने की विपल क्षमता है। यद्यपि, डिजिटल विभाजन, बाज़ार संकेंद्रण और श्रम बाज़ार ध्रुवीकरण को संबोधित करने के लिये सक्रिय उपायों के बिना, इससे आर्थिक असमता के बढ़ने का जोखिम है। नीति निर्माताओं, व्यवसायों और समाजों के लिये वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाएँ और इस डिजिटल परिवर्तन में सभी का समावेशन सुनिश्चित हो। लक्षित मध्यवर्तनों और समावेशी नीतियों के माध्यम से, डिजिटल अर्थव्यवस्था विभाजन के स्रोत के स्थान पर समता का स्रोत बन सकती है।

जैसा कि प्रसिद्ध व्यवसायी वॉरेन बफे ने कहा है :

"डिजिटल परिवर्तन वर्तमान परिदृश्य में व्यवसायों के समक्ष एक मूल यथार्थ है।"

■■■■